>

Title : Need to set up a Bundelkhand Development Authority.

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत लोक महत्व के अविलंबनीय प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी।

इस सम्मानित सदन की चर्चा से यह साबित हो गया है कि संघीय ढांचे में केन्द्र और राज्य एक दूसरे से सहयोग के बिना न तो विकास कर सकते हैं, न प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति जनता की जो अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं हैं, उनकी कसौटी पर जनता की सरकार बनकर इन कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। जैसा मुझ से पूर्व एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनके यहां सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी खुलनी हो, आईआईटी खुलना हो, उनमें केन्द्र सरकार को सहयोग करना चाहिए। बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए फण्डिंग के सम्बंध में कहा गया कि 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार दे रही है, लेकिन बाकी 25 प्रतिशत भी राज्य को नहीं देना पड़े। इस तरह जहां आज राज्य की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, प्रजातंत्र में, उस जवाबदेही को पूरा करने में भी केन्द्र से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है, तो दूसरी तरफ जहां राज्य इस बार अवर्षण की स्थिति से, देश में मानसून की कमी के कारण उत्पन्न हुई सूखे की स्थिति पैदा हुई, इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश भी भयंकर सूखे की चपेट में है, खासतौर से बुंदेलखण्ड, जहां पिछले सात वर्षों से लगातार सूखे की परिस्थिति रही है, दो लाख लोगों ने अपने परिवार की जीविका के लिए वहां से पलायन किया, लगभग 2,000 लोगों की मौत हो गयी चाहे वह कर्ज से या आत्महत्या करने स हे। इन परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 263 में स्पष्ट कहा गया है कि जहां दो राज्यों के बीच विवाद का सवाल हो या दो राज्यों के कॉमन इंट्रेस्ट्स के विकास का सवाल हो, वहां पर अन्तर्राज्यीय स्टेट काउंसिल बनाई जा सकती है। आज बुंदेलखण्ड क्षेत्र में, जिसमें कुछ उत्तर प्रदेश के जनपद हैं और कुछ मध्य प्रदेश के जनपद हैं, जहां की जमीन फट चुकी है, जहां बारिश पिछले सात वर्षों से नहीं हुई है, वहां के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से एक पहल की गयी है, राहुल जी ने पहल की है और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के इलाके को मिलाकर एक अन्तर्राज्यीय विकास प्राधिकरण बनाने की बात की गयी है। पहले जो सामरा कमेटी बनाई गयी थी, उसकी रिपोर्ट में भी यह बात थी कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड के इलाके के विकास के लिए 3,800 करोड़ रूपए और मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए 4,000 करोड़ रूपए दिए जाएं। मैं धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों को मिलाकर 8,000 करोड़ रूपए के पैकेज के साथ बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण बनाने की बात की गयी, लेकिन उसका विरोध किया जा रहा है। आज अगर 3,800 करोड़ रूपए देने की बात हो, तो मैं समझता हूं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,000 करोड़ रूपए पार्कों, स्मारकों, मूर्तियों के निर्माण में लगाया है, अगर वह राशि वे इसके लिए खर्च करते तो उनको पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। कल वहां सप्लीमेंटरी बजट पारित हुआ, सप्लीमेंटरी बजट राज्य सरकार ने उस समय पारित किया है जिस समय पूरा प्रदेश सूखे की परिस्थिति में है। जहां पहले ही राज्य सरकार 4,000 करोड़ रूपए खर्च कर चुकी है, 554 करोड़ का फिर अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न हाथी के निर्माण के लिए प्रावधान किया है।...(व्यवधान) मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। यह बात भारत सरकार के परव्यु में आती है, चुनाव आयोग एक कांस्टीटयूशन बॉडी है। आज ही चुनाव आयोग ने बहुजन समाज पार्टी को नोटिस दिया है कि दस दिन के अन्दर जवाब दें कि क्यों वे अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न को राज्य सरकार के, जनता के टैक्सेशन से उत्तर प्रदेश में निर्माण कर रही हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से पैसे का दुरूपयोग हो रहा है, दस करोड़ रूपए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, 69 करोड़ रूपए हैलीपैड बनाने के लिए प्रावधान किया गया है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please wind up now. There is a time-limit. Please take your seat. This is an issue raised in the House and the Parliamentary Affairs Minister replied to it. In spite of that, I have allowed you. You have to conclude now. The other hon. Members are also waiting. Please make it brief.

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि अगर संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय विकास प्राधिकरण बन सकता है, तो निश्चित तौर से बनना चाहिए। आज बुंदेलखण्ड के विकास के प्रति राज्य सरकार का जो एटीटयूड है, वह जनता के विरोध में है, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के विकास के विरोध में है। ...(व्यवधान)